LOK SABHA

Tuesday, April 16, 1974/ Chaitra 26, 1896 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सस्ती लागत पर विद्युत् का उत्पादन

+

*689. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में न्यूनतम लागत पर विद्युत उत्पादन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ख) विद्युत उत्पादन की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावनाएं हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) देश में संभव न्यूनतम लागत पर विद्युत उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

(1) जल विद्युत शक्यता, जो कि साधारणतया सस्ता विद्युत स्रोत है, का द्रुत विकास ।

(2) कोयला क्षेत्रों में और उस के निकट के क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों पर बृहत ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना ताकि विद्युत केन्द्र के आकार के अनुसार, जितना बड़ा हो उतनी किफायत की जा सके और परिवहन की लागत को न्यूनतम किया जा सके ।

(3) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय आधार पर विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन ताकि उपलब्ध उत्पादन क्षमता का इष्टतम तथा अत्यधिक मितव्ययी समुपयोजन किया जा सके ।

(4) देश में आवश्यक निर्माण सुविधाओं, प्रचालन संबंधी जानकारी की उपलब्धता तथा ऐसे वृहदाकार संयत्रों का समुपयोजन करने के लिए प्रणाली की क्षमता के अनुसार उत्पादन यूनिटों के बृहत्तम अनुकूल आकारों को अपनाना ।

(5) प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा भी समुन्नत प्रचालन तथा रख-रखाव, ताकि संयत्रों को मजबूत तथा रख-रखाव के लिए कम से कम बन्द किया जाए, जिस पर बहुत खर्च आता है ।

(6) संयत्र तथा उपस्कर और उनके प्रचालन की लागतों को कम करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य ।

उपर्युक्त उपायों को उत्तरोत्तर क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये पांचवीं तथा बाद की योजनाओं के दौरान भी जारी रखे जाएंगे ।

निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने का संभावित कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वे विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जो निर्माणाधीन हैं और उस के प्रचालन की संभावित तिथि:—

	(आंकड़े मिलियन किलोवाट में)					
	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	
क—जल विद्युत्						
(1) आगे ले जाई जाने वाली और चालू	0.8	1.38	4 36	0.5	1.0	5.04
(2) नई	..	..	..	..	0.01	0 01
उप-योग (क)	0 8	1.38	4.36	0.5	1.01	5.05
(ख)—ताप						
(1) आगे ले जाई जाने वाली और चालू	1.51	1.12	1.46	0 55	0 12	4.79
(2) नई	..	0 06	0 57	0 54	0 20	1 37
उप-योग (ख)	1.54	1 18	2.03	1.09	0.32	6.16
ग—परमाणु						
(1) आगे ले जाई जाने वाली और चालू	..	0.2	0.2		0 2	0.60
नई	..	.		.		.
उप-योग (ग)	..	0 2	0.2	..	0 2	0.60
कुल योग	2.34	2.76	6 59	1.59	1.53	11.81

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विवरण अभी मुझे टेबिल आफिस से मिला है, किन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सस्ती लागत पर विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो उपाय इस में दिया गया है कि जहां पर कोयले का विपुल भण्डार है, उस के नजदीक उस की स्थापना करें ताकि उस में खर्च कम हो, तो इस दृष्टि से आप ने कभी वर्क आउट कर के देखा है कि ट्रांसमीशन लाइनों में खर्च ज्यादा आता है या कोयले को दूर ले जाने में खर्च ज्यादा आता है ? क्योंकि इस में वैगन्स का सवाल भी आता है ?

दूसरा सवाल यह है कि इस में जो सुझाव दिया है, तो इस सुझाव के आधार पर पांचवीं योजना के अन्तर्गत कहां कहां पर आप का थरमल स्टेशन बनाने का विचार है और कहां पर आप ने इन को स्थापित किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि जहां कोयला पाया जाता है, उसके नजदीक अगर बिजली का कारख़ाना बनाया जाए, तो उस में आम तौर पर सस्ती बिजली बनेगी बेमुकाबले उस के कि कोयले की खानों से दूर बिजली का कारखाना हो, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रांसमीशन लाइन्स पर कितनी कास्ट पड़ती है और उस बिजली को ले जाने पर कितना खर्चा पड़ता है, उस को भी देखना होता है। जहां पर बिजली की खपत है और उस स्थान से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उस के ले जाने पर जो खर्च होता है, उस को अगर न देखा जाए तो पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी। इसलिए दोनों चीजों को देखना पड़ेगा और उनको देखने के बाद ही यह फैसला हो सकता है कि कहां पर बिजली का कारखाना बनाया जाए।

कुछ बड़े बिजली के कारखाने बनाने की हमारी योजना है और सुपर थरमल स्टेशन्स जिन को कहते हैं उन के लिए कुछ साइट्स सलेक्ट करने के लिए साइट्स छांटने के लिए एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी यह देख रही है कि वहां पर इस तरह के सुपर थरमल स्टेशनस बनाए जाएं। उस कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अपने प्रश्न के 'ख' भाग में मैंने पूछा है कि निर्माण कार्यों में काफ़ी विलम्ब हुआ है और उस का एक कारण मुझे ऐसा लगता है, यह है कि जो निर्माणाधीन कार्य हैं, यह राज्यों के बिजली बोर्डों पर छोड़ना है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस में जो यह विलम्ब हुआ है, उस के और कोई कारण हैं या यह कि राज्य सरकारों को जितनी तेजी से, जितनी चुस्ती से इस काम को करना चाहिए था उस को उन्होंने नहीं किया है। इस में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि बिजली पूरे देश में जो पैदा होती है, वह जल-विद्युत द्वारा निर्माण होती है, थरमल से उस को बनाते हैं और फिर अणु से भी इस का निर्माण करते हैं और यह कृषि, उद्योग और घरेलू इन तीन को दी जाती है लेकिन हर प्रदेश में इन तीनों उद्योगों के लिये अलग अलग दरें हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी कि इस में समान मूल्य हर प्रदेश में और हर केटेगरी के लिए रहें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हर राज्य को इस की इजाजत है इस का यह अधिकार है कि वह मूल्य निर्धारित करे और आज तो मूल्यों में अन्तर है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सब जगह बिजली के मूल्य एक ही हों, तो यह इतना आसान नहीं है। मसलन मैं आप को दो ही बातें बताऊं कि केरला में और कर्नाटक में जो बिजली पैदा होती है, वह हाइडल की बिजली है और वह सस्ती है। मध्य प्रदेश में कुल बिजली या विदर्भ में जो जो कुल बिजली पैदा होती है, वह कोयले से पैदा होती है और उस में काफ़ी अन्तर है। तो बिजली के मूल्यों में उनकी दरों में भी इन सारी बातों को देखना होगा और जब नेशनल ग्रिड बनेगा और उस के साथ साथ टैरिफ की बात

श्री डी० एन० तिवारी : पूर्वी उत्तर प्रदेश और नार्थ बिहार के लिये यही एक लिंक है जिस से वहा के यात्री सफर करते है। यदि लखनऊ से उनको ट्रेन नही मिलती है तो नार्थ बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश मे नही जा सकते हैं। क्या मैं जान सकता हू कि—इतनी भीड़ के होते हुए भी सरकार कोई ट्रेन नही चलाना चाहती है मुसाफिरो को तकलीफ देना चाहती है इस का क्या वजह है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मुसाफिरों को तकलीफ़ नही दी जा रही है बल्कि कोशिश की जा रही है कि उन को सफर की ज्यादा सुविधाये मिलें । लेकिन सब से बड़ी मुश्किल यह है कि जब तक दिल्ली मे तीसरा टर्मिनल नही बनेगा तब तक कोई भी फास्ट ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के दरमियान चलाना मुश्किल है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next question—Question No. 693. Along with that we will take up Question No. 706 also as they are identical.

Reduction in Production of Wagons in Railway Workshops

+

*693. SHRI INDRAJIT GUPTA:
SHRI M. KALYANA SUNDARAM:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have reduced the production of wagons in Railway Workshops;

(b) whether Government have increased the orders for wagons with the private wagon builders;

(c) if so, the reasons therefor and the names of private wagon builders with whom orders have been increased; and

(d) what is the capacity of these private wagon builders?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) to (d). There has been no increase in the overall orders placed on private wagon builders during 1973-74 as compared to previous years. However, m view of their better performance leading to less outstandings, the following five private wagon builders have received increased orders:—

1. M/s. Texmaco.
2. M/s. Cimmco.
3. M/s. Braithwaite
4. M/s Modern Industries.
5. M/s. Jessop & Co.

The capacity of these wagon builders is as under:

(Figures in terms of 4-wheelers)

	Licenced capacity	Installed capacity
M/s. Texmaco .	3600	3600
M/s. Cimmco .	2000	2000
M/s. Braithwaite .	3000	3000
M/s. Modern Ind. .	2000	2000
M/s. Jessop & Co. .	3279	3279

Agreement in regard to Formula for Wagon Prices

+

*706. SHRI P. M. MEHTA:
SHRI TARUN GOGOI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached in regard to the formula for wagon prices;

MR. DEPUTY-SPEAKER: The point is, if I allow a question on a particular project, then I will be opening the door for questions in regard to all the projects in India. There will be no end to it.

SHRI SAMAR GUHA: I would like to know, whether it is in the knowledge of the Government that a special plan to produce power from city waste and garbage was purchased from Skoda & Company by West Bengal Government before the War. This has not been made use of. If it is not within the knowledge of the Government, will they enquire into the matter and see that this is utilised for making power from city waste and garbage of Calcutta?

SHRI K. C. PANT: I shall have to enquire into it.

DR. MAHIPATRAY MEHTA: In the context of shortage of power, may I know whether it is a fact that many State Governments placed orders for power generation equipments with BHEL Hardwar, but they are still lying with the manufacturers as they have not been lifted. If so, may I know what action is being taken to see that this machinery is lifted and utilized for power generation to relieve the shortage of power?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is a separate question.

DR. MAHIPATRAY MEHTA: If the machinery is lifted, more power can be generated.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Regarding the lifting of machinery you have to ask a separate question.

PROF. MADHU DANDAVATE: May I know whether it is true that in the wake of increasing coal and kerosene shortage and the power crisis, scientists have now come out with techniques to exploit sun light as an alternative source of energy and, if so, whether this solar energy will be used to energise solar water heaters, solar dryers for agricultural produce, solar stills and also for domestic lighting?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a suggestion for action.

PROF. MADHU DANDAVATE: Will they take solar energy as an alternative source of energy?

SHRI K. C. PANT: There is a Power Group which is going into the question of non-traditional sources of energy. Solar energy being one of them, this subject is certainly under study in India. A small beginning was made years ago. But, then, interest flagged. Now we are trying to revive it.

SHRI R. S. PANDEY: It has been suggested on the floor of the House many a time that the crisis can be overcome by having pit-head power generating plants, especially in areas like Madhya Pradesh which have abundant supply of coal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is mentioned in the statement. It is a *suggestion for action.*

SHRI NAWAL KISHORE SINHA: May I know whether the recommendation of the Energy Commission appointed in 1965, with which foreign experts were associated, is being kept in view, particularly in the case of setting up power stations in areas where the actual supply has to be made so that there would not be long transmission lines?

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the statement the Minister has mentioned that he will do it.

SHRI K. C. PANT: In reply to a supplementary I have already stated that in the matter of location of thermal units both these factors,

namely, the proximity to the coal-bearing area and the distance to the consuming centre have to be kept in view.

Demand for Increase in Price of crude oil by Burmah Shell and Caltex

+

*690. SHRI V. MAYAVAN:
SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government fears a further increase in the prices of the crude as a result of revision of the participation agreement between Western oil companies and the Gulf Countries;

(b) whether in the wake of this agreement the Burmah Shell and the Caltex companies have demanded a raise in the oil prices with retrospective effect; and

(c) if so, the reaction of Government to their demand?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): (a) to (c). The revision of the Participation Agreement is still under negotiation between Western Oil Companies and some of the Gulf Countries. Any final agreement that may be reached in this regard is expected to be made applicable retrospectively from 1st January, 1974. The precise impact of the final agreement on the per barrel cost to the oil companies will become known only when the agreement has been finalised. However, Burmah Shell and Caltex have intimated increase in their prices provisionally in anticipation of the revision of this Agreement. Exon have also asked for price increases on this basis, but only with effect from 1st March, 1974. This matter is presently under the examination of the Government.

SHRI V. MAYAVAN: May I know from the hon. Minister the reaction of the Government. The Burmah Shell and the Caltex have intimated increase in their prices provisionally in anticipation of the revision of the Participation Agreement. Did the Government persuade these two Companies not to raise the prices unless and until the negotiations between the Western Oil Companies and some of the Gluf countries are finalised?

SHRI D. K. BOROOAH: I would like to know the exact position about the Participation Agreement between the oil companies and the oil producing countries....

SHRI V. MAYAVAN: What is the reaction of the Government?

SHRI D. K. BOROOAH: We are asking them to reconsider it.

SHRI V. MAYAVAN: Whether these two Companies will be taken over by the Government of India as in the case of Esso Company.

MR DEPUTYY-SPEAKER: That is a separate question. I think, a policy statement was made and it came out in the papers.

SHRI D. K. BOROOAH: The Government will take over these Companies as early as possible.

श्री जगन्नाथ राव मिश्र : श्रीमन् तेल-बाहुल्य देशों से हमारा जो आर्थिक सहयोग हुआ है क्या उस का अनुकूल असर तेल के मूल्य पर नहीं पड़ता है अगर हां, तो फिर बर्मा शैल और काल्टेक्स कम्पनियों के द्वारा यह मूल्य वृद्धि का प्रश्न क्यों उठता है ?

SHRI D. K. BOROOAH: The oil producing countries are selling oil on the basis of their formula accepted by them on 1st January, 1974 and they have increased what is known